**ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE**
**24, AKBAR ROAD, NEW DELHI**
**COMMUNICATION DEPARTMENT**

**Highlights of Press Briefing 07 April, 2020**

**Shri Ashok Gehlot, CM Rajasthan and Shri Randeep Singh Surjewala, In-Charge Communication Deptt, AICC addressed media today.**

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि** राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, वो आपसे आज अपने विचार सांझा करेंगे और कोरोना की इस लड़ाई में प्रदेश, राजस्थान की जनता और पूरे देश के लिए क्या सीख है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, इससे पहले कि मैं आदरणीय अशोक गहलोत जी से अनुरोध करुंगा, मैंने उनसे अनुमति ली है, आज कोरोना की इस लड़ाई में जिस प्रकार से कल केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने सासंदों की तनख्वाह में से 30 प्रतिशत कटौती कर, वो पैसा कोरोना की जंग के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जिसका श्रीमती सोनिया गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपी बहुत जल्दी हम आपको देंगे। उन्होंने 5 बड़े रचनात्मक सुझाव प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। मैं ये एक पेज का पत्र है लगभग, मैं उसका अंग्रेजी और हिंदी रुपांतरण आदरणीय अशोक गहलोत जी और पत्रकार साथियों की अनुमति से एक बार आप सबके समक्ष रखूंगा, उसके बाद अशोक गहलोत जी आपसे अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रणव झा जी आपके सवाल जो अशोक गहलोत जी से हैं, एक-एक करके हम लेंगे। मैं बगैर विलंब के आपकी अनुमति से शुरु कर रहा हूं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये पत्र अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी को लिखा है-

"In your call yesterday, you very kindly asked me to convey to you any suggestions our party has to meet the grave challenge of Covid-19. It is in this spirit that I write to you.

I hope this letter finds you safe and well during these challenging times.

I am writing to convey our support for the decision taken by the Union Cabinet to reduce salaries for Members of Parliament by 30 per cent. Austerity measures which can be used to divert much needed funds to the fight against Covid-19 are the need of the hour. In this spirit, I am writing to offer five concrete suggestions. I am certain you will find value in them.

First, Impose a complete ban on media advertisements - television, print and online - by the Government and Public Sectors Undertakings ('PSU's') for a period of two years. The only exceptions should be advisories for Covid-19 or

for issues relating to public health. Given that the Central Government currently spend an average of ₹1250 crores per year on media advertisements (not including an equal or greater amount spent by PSUs and Government companies), this will free up a substantial amount to alleviate the economic and social impacts of Covid-19.

Second, Suspend the ₹20,000 crore 'Central Vista' beautification and construction project forthwith. At a time like this, such an outlay seems self-indulgent to say the least. I am certain that Parliament can function comfortably within the existing historical buildings. There is no urgent or pressing requirement that cannot be postponed until this crisis is contained. This sum could instead be allocated towards constructing new hospital infrastructure and diagnostics along with equipping our frontline workers with Personal Protection Equipment ('PPE's') and better facilities.

Third, It makes sense to order a proportionate reduction of 30 per cent in the expenditure budget (other than Salaries, Pensions and Central Sector Schemes) for the Government of India as well. This 30 percent (i.e. ₹2.5 lakh crores per year approximately) can then be allocated towards establishing an economic safety net for migrant workers, labourers, farmers, MSME's and those in the unorganised sector.

Fourth, All foreign visits including that of the President, the Prime Minister, Union Ministers, Chief Ministers, State Ministers and Bureaucrats must be put on hold in a similar fashion. Exceptions can be made in case of special emergency or exigencies in national interest to be cleared by the PM. This amount (which is around ₹393 crores for just the Prime Minister and Union Cabinet's trips in the last five years) can be utilised extensively in measures to combat Covid-19.

Fifth, Transfer all money under 'PM Cares' fund to the 'Prime Ministers National Relief Fund' ('PM-NRF'). This will ensure efficiency, transparency, accountability and audit in the manner in which these funds are allocated and spent. It seems like a waste of effort and resources to have and create two separate silos for the distribution of funds. I understand that ₹3800 crores approximately are lying unutilised in the PM-NRF (at the end of FY2019). These funds, plus the amount in 'PM-Cares', can be utilised to ensure an immediate food security net for those at the very margins of society.

Every single Indian has made great personal sacrifices to fight this disease. They have complied with every suggestion, instruction and decision taken by your office and the Central Government. It is time that the Legislature and the Executive reciprocate this trust and good faith.

Please be assured that you have our unwavering support in meeting the grave challenge of Covid- 19 facing the country. "

इसका हिंदी रुपांतरण और अंग्रेजी रुपांतरण और पत्र की एक प्रतिलिपी, हम सब आपकी ईमेल पर अगले 5 मिनट में भेज रहे हैं। अब मैं बगैर किसी विलंब के कई बड़े कॉन्क्रीट सुझाव बहुत सारी फ्रंट पर कोविड - 19 से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए हैं और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उन पर कार्यवाही करें फौरी तौर से।

अब एक ऐसी शख्सियस्त जो राजस्थान सरकार कोरोना – 19 की लड़ाई में सबसे आगे उभरी है, मैं आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करुंगा कि पहले वो आपसे अपनी बात कहेंगे, फिर वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे।

**श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि** जैसा कि कोरोना की जो स्थिति बनी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनी थी, तो मेरा मानना है कि जिन राज्यों ने, जिन देशों ने इसको गंभीरता से लिया, वहाँ पर काफी हद तक इस पर रोक लगी और इलाज हो पाया, इसमें से राजस्थान भी एक है। हमने शुरु से ही जैसे ही पहला पेशेंट आया राजस्थान के अंदर, इटली से आया पर्यटक था, उसके बाद हमने तुरंत सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, जिसमें अनेक पार्टियां थी, उनके लीडर्स को बुलाया गया, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनसे बातचीत की गई, डॉक्टर्स से बातचीत की गई, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, सीआरपीएफ, दूरदर्शन, आकाशवाणी इन लोगों के साथ मीटिंग की गई, इस प्रकार से हमने कोशिश की। डॉक्टर्स जो एक्सपिरियंस रखते हैं, उनसे अलग मीटिंग की गई, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हेड्स को बुलाया गया। हमने इस प्रकार तैयारी की ताकि आने वाले वक्त में हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सके।

मेरा मानना है उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि अभी भी पैशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, क्वारेंटाइन हैं, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला और स्टेट लेवल पर लगातार जो हमने कोर ग्रूप बनाया है मॉनिटरिंग के लिए, तत्काल निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा हमने वॉर रुम बनाया है, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एडीएम की अध्यक्षता में। हेल्थ के लिए अलग से वॉर रुम बनाया गया है, एसीएस हेल्थ की अध्यक्षता में। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार जो स्क्रीनिंग की है, राजस्थान की आबादी करीब साढ़े 7 करोड़ है, 0.77 को हमने टच कर लिया है। इसका मतलब करीब-करीब 5 करोड़ लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर और लगभग 15 हजार टेस्ट कर लिए गए हैं, जो केरल के बाद सबसे अधिक हैं। 1 लाख बैड हमने चिन्हित कर लिए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर। 25 करोड़ रुपया इंस्टैंटली हमने हेल्थ, डॉक्टर, नर्सों के लिए रखा है। वॉर रुम के अलावा जो हमने बताया कि क्राईसिस मैनेजमेंट के लिए अलग से विंग बनाई है, मैं खुद लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं।

इस प्रकार से हमने 18 मार्च को ही सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत 20 से ज्यादा लोग इक्कट्ठे नहीं हो पाएंगे। मंदिर, मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे हैं, उनके धर्म गुरुओं से बात की गई, उनसे मीटिंग की गई। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप स्वयं अपने फोलोअर्स से अपील करें कि ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो, सोशल

डिस्टेंसिंग बहुत जरुरी है और आपको उसे मानना पड़ेगा, अल्टिमेटली सबने माना। हमने पहले से ही धारा 144 लगाकर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग शुरु कर दी थी। उसका लाभ हमें मिला था।

हमारे यहाँ पर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वाइन फ्लू के वक्त में कुछ नहीं था, तो उस वक्त में जो लैब बनाई थी, पहले पुणे और दिल्ली में सैंपल भेजने पड़ते थे, उसका फायदा भी हमें राजस्थान में मिला है। सभी सैंपल होते हैं हमारी लैब से, उसकी संख्या भी अब बढ़ा दी है, 200 से 1,500 के बीच में हो गई हैं जयपुर के अंदर भी। इस प्रकार से हमने लगातार काम करके ये स्थिति कर दी है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। अभी दो दिन पहले हमने राजस्थान के अंदर राजनीतिक दलों से बात की, हमारे चुने हुए जन प्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, करीब-करीब सबने ये कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है, जिला प्रशासन भी, पब्लिक भी, पॉलिटिशियन भी, सब पार्टियों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल राजस्थान में बन चुका है, उसी माहौल में अब लोग काम कर रहे हैं।

भिलवाडा और रामगंज जो हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय था। भिलवाडा के अंदर काफी लोग उसको एप्रिशियेट कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसमें हमने कोई घर छोड़ा ही नहीं, घर-घर के अंदर हमने करीब 3,000 टीमें बनाकर करीब 6 लाख हाउसहोल्ड तक, 32 लाख लोगों तक हम पहुंचे, और कुछ 27 केस आ गए थे, जो चिंता का विषय था। 2 की मृत्यु हुई, जो बहुत बुजुर्ग थे और बीमारी से ग्रस्त थे, बाकी सबका इलाज ढंग से चल रहा है। एक अस्पताल में जिस डॉक्टर की बेवकूफी से किसी को फैला, तुरंत हमने 18-19 मार्च में ही धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया, सीमा चाहे जिलों की हों या सिटी की, वो सब सील कर दी गई। ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं, रोड़वेज की नहीं, रेलवे पहले ही बंद हो चुका था, कमर्शियल, प्राइवेट वाहन सब पर रोक लगा दी गई।

पॉजिटिव केसेस जो थे, उन सबकी हमने मॉनिटरिंग- मैपिंग की, जब चिन्हित हो गए, उसके आधार पर हम आगे बढ़े। मैं कह सकता हूं कि भिलवाडा के अंदर जिस प्रकार से चाहे वो आईसीयू वार्ड की बात हो, 27 अस्पतालों में हमने करीब 1041 रुम को क्वारेंटाइन रुम की सुविधा उपलब्ध कराई गई, 22 होस्टल में, इंस्टिट्यूशन में करीब 12,000 रुम्स को क्वारेंटांइन रुम में तब्दील कर दिया और 20 में से 4 अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड बनाया अलग से। इस प्रकार से वहाँ पर 950 व्यक्ति क्वारेंटांइन सेंटर में हैं, 7,620 लोग होम क्वारेंटांइन में, कड़ी निगरानी के अंदर रखे हुए हैं।

इसी प्रकार से घर-घर में जरुरी फूड सप्लाई किए गए, होम डिलिवरी की गई। इस प्रकार से रुथलेस कंटेनमेंट जिसे हम कहते हैं it is the key to prevent the spread of Covid-19 in any city ये एक नारा दिया हम लोगों ने। अगर आपको कोविड- 19 से रक्षा करनी है तो रुथलेस कंटेनमेंट से आप लोग कामयाब हो पाएंगे, मेरा ये मानना है।

सोशल स्तर पर मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में लोग कॉपरेट कर रहे हैं, घरों में बंद भी हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, हमने ढाई हजार करोड़ का लोकल पैकेज दिया है, जिसके आधार पर 78 लाख पैंशनर जो थे, उनको 2 महीने की पैंशन एक साथ दे दी, उनके पास में करीब दो -दो, तीन-तीन हजार रुपए आ चुके

हैं। करीब 32 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया है, जो मजदूर भी हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, बीपीएल लोग थे, अंत्योदय योजना के, जिनको पहले 1,000 दिए, फिर 1,500 रुपए, ढाई-ढाई हजार रुपए उनके खातों में डाल दिए गए। उससे उन्हें तसल्ली हो गई और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। 10 किलो ग्राम गेहूं, पहले 5 किलोग्राम दी जा रही थी, फिर केन्द्र सरकार के घोषणा करने के बाद से 10 किलोग्राम कर दी गई। 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को, उसमें हम लोगों को फ्री दे रहे हैं, अधिकांश लोगों को और साथ में 1 किलो दाल दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के ट्रेकिंग की अलग सुविधा दी गई है, ताकि राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तब उन महिलाओं की ट्रैकिंग हो सके, उनको डिलिवरी के वक्त में कोई तकलीफ ना हो, पूरे राजस्थान में ट्रैकिंग करने का हमने निश्चिय किया। एनजीओ और सोशल वर्कर बहुत आगे आ रहे हैं, घर-घर में कोई भूखा ना रहे, ये हमारा नारा है, राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, उसमें हम कामयाब रहे हैं। इतने लोग आगे आ गए हैं, जयपुर में करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन खाने के पैकेट एनजीओ और सरकार मिलकर पहुंचा रहे हैं। बिजली या पानी के बिल भी डैफर कर दिए हैं, पशु-पक्षियों के लिए अलग व्यवस्था की गई। एक प्रकार से समझ लीजिए कि पूरी सरकार, डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोग, तमाम पार्टियों के लोग, जनता, सोशल वर्कर अपने आपको महसूस नहीं कर रहा है कि वो अलग-थलग हैं, सबने अपने आपको शामिल किया है, राजस्थान में इस माहौल में हम वायरस का मिलकर सामान कर रहे हैं।

**एक प्रश्न पर कि क्या आप लॉक डाउन 14 अप्रैल, 2020 से आगे बढ़ाएंगे या फिर चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे, श्री गहलोत ने कहा कि** जो आप कह रहे हैं वो देश के अंदर एक प्रश्न बना हुआ है, दोनों बातों का। केन्द्र सरकार क्या रुख अपनाती है, मालूम पड़ेगा 14 तारीख को। हमारा मानना है कि केन्द्र-राज्य सरकारें मिलकर नीति बना रही हैं, एक दूसरे को कम्यूनिकेट कर रहे हैं अपने-अपने व्यूज उन बातों से कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों की स्थिति अलग-अलग बनी हुई है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि किन राज्यों में कितने पेशेंट हैं। आज अभी हमारे यहाँ करीब 40 जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं। हमें जो भी पेशेंट मिलता है, एक मिले या दो मिले या तीन मिलें हम लोग उसके दो किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कार्यवाही हमारी चल रही है हमारी मुकाबला करने के लिए और उसमें हम बहुत कामयाब हैं। झुंझनू के अंदर 6 मरीज आ गए थे, तुरंत हमने पूरे एरिया को कोरड्रोन करके वहाँ कर्फ्यू लगा दिया आज उसके कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया इस प्रकार से अलग-अलग राज्यों की स्थिति अलग-अलग बनी हुई है तो सभी राज्यों को सोचना पड़ेगा, केन्द्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी।

आज भी हम केन्द्र सरकार की गाइडलाइन चाहे वो हैल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो उसको हम फॉलो कर रहे हैं और साथ में हम लोग सुझाव भी देते हैं और साथ हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें जैसे हमने पहले, सबसे पहले हम लोगों ने देश के अंदर ल़ॉकडाउन किया था। उसी रुप में हम अपना फैसला खुद ही करें जिससे की हमारी स्थिति क्या है उससे लोगों को तकलीफ भी न हो और काम धंधे बंद पड़े हैं, इंड्स्ट्रीज बंद पड़ी हैं। सरकार के रेवेन्यू का लॉस तो है ही पर मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला

बहुत अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी न हो और बार-बार लगाना भी न पड़े, ये हमारी सोच है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि आपने दो बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अधिकांश राज्यों की माली हालत खराब बताई जा रही है, क्या केन्द्र सरकार राज्यों की मदद नहीं कर पा रही, जरुरत के मुताबिक उपकरणों और संसाधनों की कमी है क्या कोरोना को लेकर भी अब सियासत होने लगी है, श्री गहलोत ने कहा कि** केन्द्र सरकार ने जो पैकेज घोषित किया वो मैं समझता हूँ कि पहला वेलकम स्टेप था, जिसने ये मैसेज दिया कि हम पैकेज दे रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सबको मालूम है कि राज्यों की स्थिति क्या बनी हुई है पहले से ही। कोविड-19 आने से पहले ही राज्यों की स्थिति पूरे देश में नाजुक बन चुकी थी क्योंकि जो इकॉनमिक स्लो डाउन चल रहा है देश के अंदर, जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे केन्द्र के पास भी, उन्होंने भी राज्यों के सब जगह पैसे रोक रखे हैं। न ग्रांट मिल रही है, न पूरे जीएटी का फंड मिल रहा है।पहले संकट में थे और लॉकडाउन के बाद आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति बनी होगी राज्यों की और केन्द्र के पास तो आरबीआई बैंक भी है, अन्य सुविधाएं है, राज्यों के पास तो कुछ भी नहीं है। अगर लोन भी लेना हो तो हमें मांग करनी पड़ती है कि आप 3 से 5 प्रतिशत कर दीजिए लोन को जो कि हमने मांग की हुई है। आरबीआई जो हमें पैसा देती है हम कहते हैं कि हमें इंट्रेस्ट भी दे दीजिए तो हमने इंट्रेस्ट के साथ में घोषणा की है अभी।

तो की सुझाव मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीसी हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि कम से कम आप एक लाख करोड़ पूरे देश के राज्यों को अलग से ग्रांट करो और साथ में आप इस प्रकार बंटवारा करो कि राज्यों में कितने पेशेंट हैं, आबादी कितनी है और जीएसटी काउंसिल की जो गाइडलाइन है या इंटर स्टेट काउंसिल की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार आप बंटवारा कर सकते हो, ये सुझाव दिया।

उसके अलावा मैंने कहा कि ये इक्विपमेंट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो पीपीई हो या पीसीआर हो लैब के लिए, जो भी इक्विपमेंट हैं, उसके सेन्ट्रलाइज्ड आप व्यवस्था करवाओ और राज्यों को दो। तो उन राज्यों को अलग-अलग कोई टेंडर की तरफ दौड़ रहा है, कोई टेंडर खत्म कर रहा है, कोई कंपनी आ गई तो उनको असुविधा हो रही है तो भारत सरकार को चाहिए कि वो सेन्ट्रली प्रदेश का जो राज्य रिसर्च का विंग है, आईसीएमआर को चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं करे, उसके बाद बंटवारा करे। इससे क्या होगा कि स्मूथली राज्यों के पास जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना उनको इक्विपमेंट मिल जाएंगे। उसी प्रकार हमने कहा कि इसेंशियल कमोडिटी का मामला है। सारा देश लॉकडाउन हो चुका है तो किस प्रकार से सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो भी मैं समझता हूँ कि हमने कहा था उनको कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आप आपूर्ति की जो श्रंखला है, उसका एक प्रोटोकॉल बन जाए, उसके माध्यम से पूरे देश में सप्लाई हो, जिससे लोगों को कोई तकलीफ न हो।हमने कई सुझाव दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे वक्त में भारत सरकार और केन्द्र सरकार, केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करें और हमारी कांग्रेस प्रेसीडेंड श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर विश्वास दिलाया प्रधानमंत्री जी को, कहा कि आप निश्चिंत रहें, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। उसके बाद मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की

ड्यूटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और सबको साथ लेकर चलें और पहले वो करें, जिसका सारे देश के लोग स्वागत करें, मेरा मानना है, उसी रुप में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।

कई मांगे ऐसी होती हैं, जैसे नरेगा मजदूर हैं, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि आप इसके लिए कम से कम 21 दिन का जो उनका पेमेंट है वो आप एडवांस कर दीजिए तो उसके उपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो गांव-गांव के अंदर कोई आदमी भूखा न सोए ये हम कह रहे हैं। ज्यादातर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में इतने स्थान पर व्यवस्था की है। लगभग हमने हर घर को टेस्ट कर लिया है। हर गरीब को टेस्ट कर लिया है। आज गरीबों के घर बैठे पैसे पहुँच रहे हैं। जिनके खाते नहीं हैं, कलेक्टर को एडवांस पहले भेज दिया गया है। वो उसको बांट रहे हैं, हजार-हजार करके बांट रहे हैं, एक-एक हजार, उसके बाद में हम और भी देंगे। इस प्रकार से आज हमारे यहाँ पूरी आम जनता चाहे वो बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय है, या मजदूर हैं उन सबकी हम रखवाली कर रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

**एक अन्य प्रश्न पर कि राजस्थान का जीएसटी समेत कुल कितना हिस्सा केन्द्र सरकार पर बनता है और आपने कितनी बार इसकी केन्द्र से मांग की है, श्री गहलोत ने कहा कि** अभी जीएसटी के आधार पर क्या मांग रहे हैं, अभी तो हम लोग जो उनको मालूम है कि जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए, अभी पिछले साल भी नहीं मिल पाया, 17 हजार करोड़ रुपए उन्होंने कम कर दिए हमारे।अभी स्थिति ये है कि जो हमने सुझाव दिए हैं, उनको एक लाख करोड़ रुपए की। आरबीआई के माध्यम से बिना इंट्रेस्ट लोन की मांग की बात कही है। हमने कहा कि जीडीपी का जो आप तीन प्रतिशत देते हो उसको पांच प्रतिशत करो, हमें लोन की बहुत जरुरत है, इस प्रकार की हमने मांग की है। अभी उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आया है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि दिल्ली औऱ महाराष्ट्र में जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं क्या राजस्थान में भी ऐसा है, श्री गहलोत ने कहा कि** मेरा मानना है कि ये तबलीगी जमात का जो मामला हुआ है दिल्ली में, पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा मुद्दा बन गया और सब राज्यों में और कई राज्यों में इनके तबलीगी जमात के जो लोग गए हैं पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत सीरीयस मामला है और ये ऐसा मामला बन गया है कि गलती किसकी रही है वो भी देखना पड़ेगा। देश के अंदर हम लोग एक तरफ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, फारसी, जैन सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बीच अगर किसी ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए, मुकदमें दर्ज होने चाहिए औऱ अगर मान लो कोई आयोजन करे तो आप रोक देते आप कड़े से पेश आते, कौन आपको मना कर सकता था।

मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज का सिटिंग जज है, जांच होनी चाहिए इतना बड़ा मुद्दा देश में, दुनिया में बन चुका है तो मतलब सच्चाई देश के सामने क्यों नहीं सामने आए, जिससे कि आप अगर किसी ने बेईमानी की है, आरोप लग रहे हैं आप उनको बैन कर दीजिए कौन मना करेगा आपको आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, जेल भेज दीजिए और मान लीजिए उन्होंने इतल्ला की टाइमली, और एसडीएम ने कार्यवाही नहीं की, डीएम ने कार्यवाही नहीं की, पुलिस ने कार्यवाही नहीं की रेगुलेशन वाले वहाँ जा रहे हैं, सैम्पल लेकर आ रहे हैं, फिर भी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोई उपयुक्त विचार होना चाहिए जब जाकर कोई सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि ये ऐसा

मुद्दा बन गया है, पूरे देश के लोगों में एक तरह का माहौल बना दिया गया है। जो कि आज कोविड-19 का मुकाबला करने के माहौल में उचित नहीं कहा जा सकता, ऐसा मेरा मानना है।

**श्री सुरजेवाला ने जोड़ा कि** आपकी अनुमति से इसमें जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कहा और तबलीगी जमात पर प्रश्न था, मैं फिर पार्टी की ओर से कहना चाहूँगा। तीन या चार बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दिन से ही कहा, वो तबलीगी जमात हो, वो कोई और समूह, व्यक्ति, धड़ा या संस्था हो, जो कोई भी लॉकडाउन का अगर किसी ने उल्लंघन किया है, या फिर टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग किया है तो देश के कानून के अनुरुप बगैर कोई बात देखे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें पूरा देश इकट्ठा है, कोई शक-शुभा की गुंजाइश नहीं। पर दो या तीन प्रश्नों का जवाब मीडिया के साथियों को भी सरकार से पूछना पड़ेगा।

1. तबलीगी जमात को 15 या 16 या 17 मार्च को वो सारा जमावड़ा करने की इजाजत, अनुमति किसने दी थी? हम जानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, भारत सरकार और आदरणीय केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के नीचे आती है। ऐसे में क्या सरकार ने आजतक ये बताया कि तबलीगी जमात को वो जमावड़ा करने की इजाजत दी ही किसने? जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की साझेदारी वाली सरकार ने इस प्रकार की इजाजत देने से इंकार कर दिया था?

2. क्या केन्द्रीय गृहमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निजामुद्दीन रात के दो बजे भेजा? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों?

3. ये सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी, रात को वहाँ एक मौलाना साहब से मिलने गए थे, क्या अजीत डोभाल जी और केन्द्रीय गृहमंत्री बताएंगे कि वो मौलाना साहब से रात को दो बजे क्यों मिलने गए थ और उसके बाद वो मौलाना फरार क्यो हैं? इस बात की भी जरुर सरकार को जांच कर कार्यवाही करनी चाहिए। क्या वार्तालाप केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय अजीत डोभाल जी और वहाँ जमात के जो निजामुद्दीन में लोग थे, उनके बीच हुआ? मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच मे इन दोनों-तीनों पहलुओं की जांच भी आवश्यक है और सरकार को खुले मन से बाहर आकर इस बारे में जवाब देना चाहिए।

**On another question that will the decision to allow export of essential medicines impact the preparedness of states in fighting Covid-19 also, are you satisfied about the availability of PPEs and other self care equipments, Shri Gehlot said-** राजस्थान में तो हम लोगों ने काफी इंतजाम कर रखा है। उसके बाद भी हम लोग और कोशिश कर रहे हैं एक तो किस प्रकार से रैपिड टेस्ट हो उसक लिए हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, पीपीई इक्विपमेंट हो, या कोई भी हो, हम लोगों ने इसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। इक्विपमेंट में हम कमी नहीं आने देंगे, टाइमली चीन से भी औऱ अन्य मुल्कों से भी बात हो रही है। 5-4 दिन में और किट्स आ जाएंगी तो जांच भी होगी और डॉक्टर्स का नर्सेस की सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करते हुए राज्यों की जरुरतों को जरुर ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपोर्ट भी काफी किया गया। ये समझ के परे है आज भी समझ में नहीं आता, मीडिया में जब

आप लोग लिखते हैं कि पिछले दिनों में भारी संख्या में पीपीई और वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, दूसरे मुल्कों को ये समझ के परे हैं, इसका स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि मुख्यमंत्री जी किसानों के खेतों में खड़ी फसलें समेटने और अगली बिजाई करने में काफी समस्याएं आ रही हैं। बहुत से किसान एक से दूसरे इलाके में जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ जाने पर काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, वहीं उन्हें खाद, बीज व फसल निकालने के लिए मशीनों की किल्लत महसूस हो रही है। सब्जी बेचने वाले किसानों की हालत तो और भी खराब है क्योंकि मंडियों तक खुदरा ग्राहक भी नहीं पहुँच पा रहा है, श्री गहलोत ने कहा कि** इसके बारे में हम लोग खुद चिंतित हैं। अभी हम लोग कुछ मंडियाँ भी खोल रहे हैं क्योंकि उनका एमएसपी से धान खरीदना भी था हम लोगों को, उसके अंदर भी परेशानी आ रही है और अभी जब रबी की सीजन जा रही है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं क्योंकि जो कंपनी है, ट्रैक्टर। जैसे टाफे ट्रेक्टर की कंपनी है, उन्होंने ऑफर किया है कुछ ट्रैक्टर भी, इक्विपमेंट भी किसानों की मदद के लिए इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि किसानों को जो तकलीफ आ रही है वो गाइडलाइन भी हमने जारी की है और पंजाब से जो मशीनें आती हैं खेत कटाई के लिए उसका भी इंतजाम किया, पंजाब के सीएम से भी हमने रिक्वेस्ट की है, इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं।

**एक अन्य प्रश्न पर कि राजस्थान में हम लोग रैपिड टैस्टिंग कब से देखने वाले हैं, हम कब रैपिड टैस्टिंग करेंगे, श्री गहलोत ने कहा कि** अभी 7-8 दिन लग जाएंगे। आज हम ये आर्डर देने जा रहे हैं 10 लाख किट का, तो हमें उम्मीद है कि 7-8 दिन में वो सब व्यवस्था हो जाएगी और चीन से आएगा उसके बाद हम बड़े स्केल में रामगंज जो एरिया है हमारा हॉट स्पॉट बना हुआ है जयपुर के अंदर, हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं वहाँ पर।

**एक अन्य प्रश्न पर कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सरकार से एक रिटैलिएशन की बात की है, वो दवाइयों से अनुबंध की बात कर रहे थे, उस पर वो कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, श्री सुरजेवाला ने कहा कि** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इसका सबसे सार्थक जवाब दिया है। एक मानवीय तरीके से हम हमारे सब मित्रों की मदद करेंगे। पर पहली मदद हर भारतीय की करेंगे। भारतीयों की जान जोखिम में डालकर विदेशों में दवाई सप्लाई नहीं की जा सकती। अमेरिका हमारा मित्र है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी को कोई अधिकार नहीं कि वो भारत से धमकी भरी भाषा में बात करें या भारत पर और भारत सरकार और प्रधानमंत्री पर दवाब डालकर जीवन रक्षक दवाइयों के निर्यात को, जो भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, उसके निर्यात को खुलवाएं। हमें उम्मीद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कूटनीतिक रणनीति के अनुरुप इस धमकी भरे लहजे का संज्ञान भी लेंगे और भारतीयों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे।

**एक अन्य प्रश्न पर कि अब जैसे स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में है और लॉकडाउन को खोलने की बात चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन खोलने की स्थिति है या नहीं और दूसरा क्या सेंटर को इस डिसीजन लेने में स्टेट के साथ कंसल्ट करने के बाद ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। कुछ**

**मुख्यमंत्रियों ने ऐसी बात कही हुई है, श्री गहलोत ने कहा कि** मैं समझता हूँ कि 21 दिन बहुत ज्यादा होते हैं पब्लिक को आप घरों में रखें। लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियाँ, सारे छोट-बड़े उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। आर्थिक रुप से हम किस दिशा में जा रहे हैं आप समझ सकतें हैं, पूरा मुल्क चिंतित है, आम जनता चिंतित है, हम सब चिंतित हैं। परंतु जिंदगी औऱ जीवन बचाना भी बहुत आवश्यक है तो मेरा मानना है कि हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते इमीजिएटली जिससे की जीवन खतरे में पड़ जाए। इसलिए हमने दो टास्क फोर्स बनाई है, पीएम के साथ जब वीसी हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि हमें राज्यों की क्या भूमिका है या राय हो वो जानना चाहेंगे, पीएम भी, तो हमने दो टास्क फोर्स बनाई है, जिनमें कि लॉकडाउन कैसे खुले, किस फेजेज में खुले और दूसरा आर्थिक सुधार कैसे हो, अर्थव्यवस्था की इस पटरी पर कैसे वापस आएं, दोनों बातों को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई है, जो हमारे हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, मिस्टर अरविंद मायाराम हैं , जो पहले हमारे केन्द्र में फाईनेंस सेक्रेटरी थे, उन अध्यक्षता में एक हमारे खुद के यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये काम देख रहे हैं किस रुप में उनकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।

मेरा मानना है कि जीवन बचाना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा बहुत गंभीरता से। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक दम से लॉकडाउन विदड्रो कर लें। विदड्रो नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, तो फेजेज में ही करना पड़ेगा, मेरा ये खुद का कॉमनसेंस कहता है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि क्या कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के सुझाव को आप लोग अपनी राज्य सरकारों में भी, खासतौर से राजस्थान सरकार में फॉलो करेंगे, कि क्या आप दो सालों तक मीडिया के विज्ञापन पर और विदेश यात्राओं पर रोक लगाएंगे, श्री गहलोत ने कहा कि** कांग्रेस प्रेसीडेंट ने लैटर लिखा है, आप सोच सकते हैं, सोच समझकर लिखा हैं। क्योंकि इन दोनों मामलों में अति हो गई थी, पूरा मुल्क जानता है कि अति हुई थी, लोगों में चर्चाएं थी ये विवाद का विषय बन गई थीं दोनों बातें इसलिए उन्हें लिखना पड़ा है। तो राज्य सरकारें भी जितना संभव होगा वो उस लाइन पर ही चलेगी आगे भी, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ।

**श्री सुरजेवाला ने जोड़ा कि** अगर आपने ये ध्यान दिया हो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने केन्द्र सरकार को एडवर्टिजमेंट्स और केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों को विदेश यात्राओं को लेकर सुझाव दिया है। एडवर्टिजमेंट्स को लेकर प्रान्तीय सरकारों को अपने विवेक से ये निर्णय लेना होगा, लगभग-लगभग 4 हजार करोड़ से अधिक रुपया हर साल केन्द्र सरकार उनकी पीएसयू और सरकारी कंपनीज और कुछ साथी ये भी कहते है कि ये रुपया 5 हजार करोड़ से भी अधिक खर्च करते हैं। एमपीज अपनी सैलरीज मे कट ले रहे हैं। आज जब लोगों की रोटी और रोजगार जा रहे हैं तो आज सारा पैसा कोविड -19 से जो स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों की लड़ाई है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 हजार करोड़ रुपया जो संसद के नए दफ्तर बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं, उसको भी फौरन खारिज कर इनसे अस्पताल और पर्सनल प्रोटेक्श्न इक्विपमेंट की राय दी। भारत सरकार का वो सारा खर्चा अगर आप केन्द्रीय स्कीम जो हैं, उनको निकाल दें, सैलरी और पेंशन को निकाल दें तो अगर 30 प्रतिशत बाकी के खर्चे पर कट लगे तो वो बहुत बड़ी राशि ढाई लाख करोड़ की बनती है, उससे माइग्रेंट लेबर, वर्कर, नरेगा

वर्कर, किसान अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन सबको एक सोशल सिक्योरिटी नेट दी जा सकती है। इसके बारे में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सुझाव दिया है।

पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में 3,800 करोड़ रुपए के करीब 2019 के आखिर तक पड़ा था। मुझे किसी आप जैसे मित्र ने बताया कि पीएम केयर में भी 5 हजार करोड़ रुपए के करीब है, अगर इस किटी को जोड़ लें तो ये लगभग 9 हजार करोड़ रुपए की किटी हो जाती है। इसका इस्तेमाल भी कोविड-19 से लड़ने में हो सकता है और उसका बकायदा प्रोपर ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी। ये और बड़े सुझाव हैं जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए हैं।

**एक अन्य प्रश्न पर कि जो भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसका आइडिया कहाँ से आया क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, रेंडम टेस्टिंग होनी चाहिए उसके ऊपर तो क्या वहाँ से भी क्या उनका सजेशन भी उसमें शामिल था, श्री गहलोत ने कहा कि** श्री राहुल गांधी ने तो 12 फरवरी, 2020 को ही कह दिया था, भारत सरकार को आगाह किया था, अगर उस वक्त हम लोग ध्यान देते अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का, और अधिक कदम उठाते तो मेरे ख्याल से स्थिति दूसरी होती औऱ उसके बाद में श्री राहुल गांधी की अभी वीसी हुई थी, वर्किंग कमेटी के समय तब भी उन्होंने कहा था कि इसके लिए रैंडम सैंपल लिए जाने चाहिए। राजस्थान सरकार उस काम में लगी हुई है, काफी जगह रैंडम सैंपल लिए गए हैं आगे भी लिए जाएंगे, रखना चाहिए राज्यों को, जिससे कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं तो क्या स्थिति बनेगी मजदूरों की, क्या स्थिति बनेगी हैंड टू माउथ की, किस प्रकार से उद्योग शुरु होंगे, क्योंकि बिजली कंपनी हो, चाहे वो उद्योग धंधे हों, सब जगह जो आज स्थिति बनी हुई है उस वापस पटरी पर लाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए बिना केन्द्र की मदद के संभव नहीं हो पाएगा और तकलीफ पाएंगी राज्य सरकारें।

**एक अन्य प्रश्न पर कि अगर राज्यों को जीएसटी का शेयर समय पर नहीं मिलता है, तो क्या राजस्थान में रिलीफ वर्क पर भी कोई असर पड़ सकता है, श्री गहलोत ने कहा कि** बड़े रुप में तो वर्क पर फर्क पड़ता ही है। अभी जो डिजास्टर फंड है, वो रिलीज हुआ है राज्यों को 600 करोड़ रुपए राजस्थान को मिले हैं, उससे काम चला रहे हैं। पर अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगी स्थिति कोई कुछ कह नहीं सकता। उसमें तो बिना केन्द्र की बड़ी मदद के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू तो खुद आना बंद हो गया राज्यों को तो, जब सड़कें सूनी पड़ी हैं, इंडस्ट्री बंद हैं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा?

**On another question that the Government of India has allowed partial export of chloroquine on a case to case basis after the retaliatory threat from the US President, how do you see this action on the part of the Government of India, Shri Surjewala said-** Former Congress President Shri Rahul Gandhi has articulated the India's stance and national interest in the most appropriate fashion. As a part of the entire world community, we will help all our friends, however, the first right on India's resources as also life saving medicines to fight Corona remains of the 130 crore Indians. Our friends can request us, but, no one can threaten India. The language used by our common friend United

States of America, whose friendship, we cherish, both as a party and as a nation, is unwarranted and absolutely incorrect.

The American President has made a request to the Indian Prime Minister, we expect Indian Prime Minister to take any such decision by keeping 'India first and Indians first' policy when it comes to the export of essential and life saving medicines including chloroquine and hydroxychloroquine and other medication. It may call that Prime Minister will have to take and we sincerely hope that Prime Minister will appropriately register his protest and remarks and take any call on export of medication by keeping India and Indians first.

**एक प्रश्न पर कि इस लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी तरफ से जिस तरह से डॉक्टरों, नर्सों का आभार व्यक्त करने के लिए थाली बजवाई, दीए जलवाए, क्या राजस्थान में ऐसा करने से वाकई में कुछ फर्क पड़ा है, श्री गहलोत ने कहा कि** उनके द्वारा मैसेज देने की बात थी, जबसे ये कोरोना का चैलेंज सामने आया है तो मैं समझता हूं कि पूरी सोसाईटी ही स्वत: ही आज डॉक्टरों, नर्सों के साथ में खड़ी है और सभी डॉक्टरों, नर्सों को मालूम है कि आज सरकार का, समाज का, सबका हमें सहयोग मिल रहा है और हमारे बारे में लोगों का ओपिनियन क्या है, उसको वो महसूस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसा रिवाज हो, उनको अपनाने की बात की हो, कोशिश की हो। पर मेरा मानना है कि कुछ लोगों ने, जिस-जिस ने इस बात को माना भी है, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके सड़कों पर आ गए, जुलूस निकालने लग गए थे, वो भी देखा हम लोगों ने, तो ये अपने-अपने अलग-अलग तरीके हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता।

**एक अन्य प्रश्न पर कि संविदा कर्मियों की भूमिका, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की भूमिका को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, श्री गहलोत ने कहा कि** अभी जो सरकार में काम कर रहे हैं, सभी, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, स्थाई हों, अस्थाई हों, सभी मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा माहौल कभी देखा नहीं है हमने। राजस्थान में हर वर्ग, चाहे ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, सब लोग लगे हुए हैं अपने हिसाब से और अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मुकाबला सभी मिलकर कर रहे हैं, तभी विजय प्राप्त होगी। ये एक बड़ा चैलेंज है और पब्लिक को खुद बाहर जाना पड़ेगा सहयोग करने के लिए। स्क्रीनिंग करेंगे पब्लिक को, तभी जाकर कंट्रोल हो पाएगा।

**एक अन्य प्रश्न पर कि पूरे देश ने भीलवाड़ा का उदाहरण देखा है जिस तरह से आपकी सरकार ने वहाँ पर काम किया है, अब लॉकडाउन खुलने वाला है, उस पर क्या सोचा है आपने, दूसरा सवाल ये है कि जमात के कार्यक्रम से जो स्थितियां बिगड़ी हैं, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्या कहेंगे, श्री गहलोत ने कहा कि** अगर लॉकडाउन खुलेगा तो एक साथ नहीं खुलने वाला है, हमने 40 जगह कर्फ्यू लगा रखे हैं, तुरंत तो एक साथ में खुलेगा नहीं। चाहे भीलवाड़ा हो या कोई भी जगह हो, इसे हमें फेज वाइज खोलना पड़ेगा, ये निर्णय करने की घड़ी आने वाली है, अभी आई नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो भी फैसले होंगे वो सोच-समझ कर ही होंगे।

**एक अन्य प्रश्न पर कि लॉकडाउन अगर खुलता है, तो आपकी क्या रणनीति है कैसे खोलेंगे, श्री गहलोत ने कहा कि** मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमने टीम बना रखी हैं, एटीएस होम की अध्यक्षता में। वो इस काम को देख रही है कि किस प्रकार से किस फेज में कैसे खोलें। पीडीएस सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं, गांव के अंदर भी राशन सप्लाई हो रहा है, बाकी जो दुकानें हैं, उनको भी हमने अलाउ कर रखा है, इस तरह से ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से हम खोलेंगे, हम चाहेंगे कि इस तरह से खुले कि जो लॉकडाउन बना रहा है, उसका इम्पेक्ट बना रहे और आगे हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैंटेन कर सकें। डिपेंड करेगा कि क्या फीडबैक आता है राजस्थान के अंदर से, तो कम्यूनिटी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।

**एक अन्य प्रश्न पर कि जहाँ पर भीलवाड़ा मॉडल को अन्य राज्य भी कॉपी कर रहे हैं, सक्सेसफुल मॉडल माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रामगंज में 36 केस रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ का क्या स्टेटस है, श्री गहलोत ने कहा कि** वही जो हमने कहा, ruthless containment is the key to prevent the spread of Covid-19 in any city तो भीलवाड़ा का जो मॉडल है, वही काम में लिया जा रहा है जयपुर, रामगंज के अंदर भी। कल ही हमने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को इंचार्ज बनाया है अलग से और हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं रखेंगे हम उसके लिए। ये हमारे लिए अभी प्राथमिक जॉब है।

**Sd/-**<br>
**(Vineet Punia)**<br>
**Secretary**<br>
**Communication Deptt,**<br>
**AICC**